घंटों बारिश में प्रदर्शन करने को मजबूर हुए 450 छात्र-छात्राएं, जांच में सही मिली शिकायतें

एकलव्य विद्यालय बिजोरी में खाने का संकट: ठेका खत्म होते ही बिगड़ी व्यवस्था, छात्रों का फूटा गुस्सा

हरिभूमि न्यूज ⏭ तामिया, बाबा ठाकुर

जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बिजोरी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला छात्रावास में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता का है।

सोमवार को भोजन की खराब गुणवत्ता से नाराज छात्र-छात्राओं का आक्रोश उस समय खुलकर सामने आ गया, जब उन्होंने विद्यालय परिसर में बारिश के बीच घंटों प्रदर्शन कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुशवाहा पर तानाशाही रवैया अपनाने और लगातार घटिया भोजन परोसने के आरोप लगाए।

छात्रों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से छात्रावास में उन्हें बेहद खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा था। दाल इतनी पतली परोसी जा रही थी कि वह पानी जैसी दिखाई दे रही थी। सब्जियों में कीड़े-मकोड़े निकलने की शिकायत भी छात्रों ने की। इतना ही नहीं, छात्रों के अनुसार पिछले चार दिनों से भोजन के नाम पर केवल पुलाव और अचार ही परोसा जा रहा था। लगातार एक जैसा और निम्न गुणवत्ता का भोजन मिलने से छात्रों में नाराजगी बढ़ती गई और आखिरकार वे आंदोलन करने को मजबूर हो गए।

कलेक्टर तक पहुंची शिकायत, जांच में सही मिलीं शिकायतें

छात्रों के प्रदर्शन की सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची। शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल तामिया तहसीलदार को विद्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने विद्यालय के मेस का निरीक्षण किया और छात्रों से चर्चा की। प्रशासनिक जांच के दौरान भोजन की गुणवत्ता को लेकर छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। निरीक्षण के दौरान मेस की व्यवस्थाओं और परोसे जा रहे भोजन पर भी सवाल खड़े हुए।

ठेका समाप्त होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने संभाली रसोई

जानकारी के अनुसार, पिछले कई वर्षों से विद्यालय में भोजन व्यवस्था ठेकेदार के माध्यम से संचालित होती थी। अप्रैल माह में भोजन आपूर्ति का अनुबंध समाप्त हो गया। इसके बाद नया ठेका समय पर नहीं हो सका। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन ने स्वयं भोजन व्यवस्था संचालित करने का निर्णय लिया।विद्यालय में लगभग 450 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनके लिए प्रतिदिन बड़ी मात्रा में राशन, सब्जी और अन्य खाद्य सामग्री की खरीद की जाने लगी। इसी अवधि से भोजन की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आने लगीं।

अनुभवहीनता या लापरवाही?

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि भोजन व्यवस्था का संचालन सीधे विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए जाने के बाद गुणवत्ता में लगातार गिरावट आई। पहले जब भोजन व्यवस्था ठेकेदार के माध्यम से संचालित होती थी, तब इस प्रकार के विवाद सामने नहीं आए थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भोजन व्यवस्था के संचालन में अनुभव की कमी रही या गुणवत्ता नियंत्रण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।छात्रों की शिकायतों के अनुसार, मेस में परोसी जा रही दाल अत्यधिक पतली थी और सब्जियों की गुणवत्ता भी खराब थी। यदि ऐसा है, तो यह केवल व्यवस्थागत कमी नहीं बल्कि निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।

खरीद प्रक्रिया पर भी उठ रहे सवाल

मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू खाद्यान्न और अन्य सामग्री की खरीद को लेकर सामने आ रहा है। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोजन सामग्री की खरीद में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। यह भी आरोप है कि बिना पर्याप्त प्रतिस्पर्धी कोटेशन के किराना सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदी की गई।इसी प्रकार सब्जियों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई बार ऐसी सब्जियां परोसी गईं जिनमें कीड़े मिले। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह आपूर्ति और गुणवत्ता परीक्षण दोनों स्तरों पर गंभीर लापरवाही का मामला हो सकता है।हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और इनकी जांच होना शेष है।

छात्रों की मांग

मिले गुणवत्तापूर्ण भोजनआंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें केवल गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन चाहिए।

उनका कहना है कि आदिवासी विद्यार्थियों के लिए संचालित इस आवासीय विद्यालय में भोजन जैसी बुनियादी सुविधा में भी समझौता किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।अब छात्रों और अभिभावकों की निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर भोजन व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करता है, तो न केवल विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भी रोकी जा सकेगी।

नियमों के पालन की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि विद्यालय में अप्रैल माह के बाद की गई सभी खरीद प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि खाद्यान्न, सब्जी और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीदी शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार की गई या नहीं। साथ ही यह भी सामने आएगा कि क्या सप्लायरों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्तों का पालन किया गया।यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

पहले भी विवादों में रहा है विद्यालय

बिजोरी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इससे पहले भी विभिन्न कारणों से सुर्खियों में रहा है। पूर्व में भी छात्रावास की व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में भोजन व्यवस्था को लेकर हुआ यह ताजा विवाद विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नए सिरे से सवाल खड़े कर रहा है।

कबाड़ कक्ष में फंदे से लटका मिला शव

पुलिस चौकी में होमगार्ड जवान ने लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस

हरिभूमि न्यूज ⏭ परासिया/जुन्नारदेव

जुन्नारदेव थाना क्षेत्र की गुढ़ी अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ होमगार्ड जवान दिलीप बाथरे ने चौकी परिसर स्थित कबाड़ कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, दिलीप बाथरे बड़कुही निवासी थे और लंबे समय से गुढ़ी अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ थे। वे अपने मिलनसार और शांत स्वभाव के लिए क्षेत्र में जाने जाते थे। गुरुवार को उनका शव चौकी परिसर के कबाड़ कक्ष में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही एसडीओपी सोनम पाटिल, थाना प्रभारी जे. मसराम एवं उप थाना प्रभारी मुकेश डोंगरे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी है। दिलीप बाथरे अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गए हैं।

पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

कुम्हार समाज के मोक्षधाम में बनेगा सामुदायिक भवन

सिंगोड़ी। ग्राम पंचायत सिंगोड़ी की नई आबादी स्थित कुम्हार समाज के मोक्षधाम में जल्द ही सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। जनपद पंचायत अमरवाड़ा के जनपद सदस्य एवं कृषि स्थायी समिति के सभापति योगेश यादव ने अपनी जनपद निधि से 4 लाख 4 हजार रुपये की लागत से बनने वाले भवन का विधि-विधान के साथ भूमिपूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।यह सामुदायिक भवन मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के दौरान आने वाले परिजनों एवं ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। भवन बनने से लोगों को बैठने, विश्राम करने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से इस भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।भूमिपूजन कार्यक्रम में योगेश यादव ने कहा कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देना उनकी प्रतिबद्धता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सामुदायिक भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।कार्यक्रम में सरपंच कपिल ठाकुर, कुम्हार समाज के अध्यक्ष नारायण प्रजापति, नवीन जैन, गगन जैन, हुकम प्रजापति, मेहताब मालवीय, सुरेश प्रजापति, राजू प्रजापति, सतीश प्रजापति सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग एवं ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने इस जनहितकारी पहल के लिए जनपद सदस्य योगेश यादव का आभार व्यक्त किया।

बड़े निर्माण कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी

कलेक्टर ने ली विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। यह बैठक दो सत्रों में आयोजित की गई थी जिसमें प्रथम सत्र में सड़क संबंधी विभागों में लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, एम.पी.रोड डेव्लपमेण्ट कार्पोरेशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई, तो वहीं दूसरे सत्र में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों, जिनमें म.प्र. भवन विकास निगम, लोक निर्माण विभाग (भवन), जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन और प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नवीन शैक्षणिक अस्पताल एवं अन्य भवनों और नवीन जेल कॉम्प्लेक्स के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की।

कलेक्टर श्री नारायन ने सभी निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में गति लाएं और गुणवत्तापूर्वक निर्माण, निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित कराएं। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों के साथ ही पूर्ण हो चुके कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी फ़ील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ठेकेदार के साथ ही निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार एवं सड़क और भवन निर्माण से संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। विभागों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक - एक निर्माण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश भवन विकास निगम सिवनी द्वारा जिले में कुल 9 कार्य किये जा रहे हैं। जिनमें सांदीपनि विद्यालय परासिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है, फिनिशिंग वर्क और हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगतिरत है। यहां के 100 सीटर बालक एवं 100 सीटर बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटन एवं टेंडर की प्रक्रिया प्रचलन में है। तहसील कार्यालय जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा नगर, परासिया व अमरवाड़ा का कार्य प्रगतिरत है। चौरई कॉलेज की बाउंड्री वॉल पूर्ण हो चुकी है। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में स्वीकृत 786 लाख रूपये लागत के इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रचलन में है।

19 निर्माण कार्यों पर हुआ विचार विमर्श

बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मार्गों की कुल संख्या 276 और कुल लंबाई 1227.07 कि.मी. है। वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के मुख्य बजट में 118.85 कि.मी. लंबाई (लागत 210.69 करोड़) के 19 कार्य सम्मिलित किए गये हैं। इनमें ग्राम धवईधान से नन्दोरी होते हुए जमनाही तक सड़क, बींझावाड़ा से बिलंदा मार्ग, झिरना से कोसमढाना मार्ग हर्रई, चारगांव से मिलमाढाना मार्ग, ग्राम खैरवाड़ा से ग्राम गुरैया मार्ग, अनखावाड़ी पगारा जामुनबर्रा-लोनापठार-कोहका-दमुआ मार्ग 4 स्लैब कलवर्ट सहित, जाटला पहुंच मार्ग 4 पुलिया सहित, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग 547 से जमुनिया महादेव मेला मार्ग, राजाखोह पहुंच मार्ग, नवेगांव स्टेशन पहुंच मार्ग, लेनियामारू बिलवा मार्ग, गोपालपुर आमाखोह मार्ग, नन्दोरा पहुंच मार्ग, करमोहनी बंधी पहुंच मार्ग, दातलावाड़ी सरेखाढाना मार्ग, मांडी झोतकलाँ मार्ग पर स्लैब कन्वर्ट निर्माण, बीजेपानी कोटलबर्री मार्ग, छिंदी नागरी धोरावाड़ी झिरना धनोरा बिछुआ जुंगावानी मार्ग और राज्य मार्ग क्र. 46 पर स्थित ग्राम चाँद से चन्दनगांव- बाढगाँव- लालगांव-मेघढोन थोछी - जमतरा (पेंच राष्ट्रीय उद्यान) मार्ग शामिल हैं।

झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई, अवैध क्लिनिक सील

छिन्दवाड़ा। कलेक्टर हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार एवं एसडीएम अमरवाड़ा श्री हेमकरण धुर्वे के मार्गदर्शन में तहसील अमरवाड़ा के ग्राम पौनार में गैर-मान्यता प्राप्त डॉक्टर (झोलाछाप) के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रवीण बंजारा (उम्र 26 वर्ष) बिना किसी वैधानिक डिग्री के क्लिनिक का संचालन करते पाया गया। इस पर राजस्व, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक योग्यता एवं अनुमति के चिकित्सा कार्य करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

10 वाहनों से की गई 81000 रूपये की चालानी कार्रवाई

छिन्दवाड़ा। परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर हरेंद्र नारायन के आदेश के परिपालन में मंगलवार को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनुराग शुक्ला के निर्देशन में परिवहन विभाग के विशेष जांच दल द्वारा सांवरी-उमरेठ क्षेत्र में संचालित वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया।

सांसद बंटी विवेक साहू ने केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात

छिंदवाड़ा। सांसद बंटी विवेक साहू ने नई दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य मुलाकात की है। इस दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा और पांढुर्णा संसदीय क्षेत्र के कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विस्तृत चर्चा की है, साथ ही सांसद श्री साहू ने छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के क्षेत्रहित से संबंधित महत्वपूर्ण मांगों एवं जनहित के मुद्दों को भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद बंटी विवेक साहू को छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विकास कार्यों को लेकर हरसंभव सहयोग देने को आश्वासन दिया है। सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के विकास को लेकर दिये गये मार्गदर्शन एवं स्नेह के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय से आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू के साथ में जबलपुर सांसद आशीष दुबे भी मौजूद थे।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई : दूध, खोआ और पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए

छिन्दवाड़ा। आमजन को सुरक्षित एवं बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ, दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर श्री धीरेंद्र सिंह की निगरानी में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिलेभर में लगातार निरीक्षण, निगरानी एवं नमूना संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा दल ने गोकुल डेयरी, खापाभाट छिंदवाड़ा का निरीक्षण कर दूध के दो नमूने एवं खोआ का एक नमूना संग्रहित किया। वहीं शिवोम एग्रो इंडस्ट्री, खजरी छिंदवाड़ा से पनीर का एक नमूना तथा अमरवाड़ा दूध संकलन केंद्र से दूध के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए। संग्रहित सभी नमूनों को परीक्षण के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, इंदरगाह भोपाल भेजा गया है। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रूपराम सनोडिया एवं श्री पंकज घाघरे शामिल थे।

किराना दुकानों में खुलेआम शराब बेचने का आरोप, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

सलखनी में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

हरिभूमि न्यूज ⏭ चौरई

ग्राम पंचायत सलखनी में कथित रूप से किराना दुकानों से हो रही अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तीरथ ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चौरई को ज्ञापन सौंपकर गांव में संचालित चार किराना दुकानों पर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिससे गांव का सामाजिक वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है।ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि गांव की चार किराना दुकानों से खुलेआम शराब बेची जा रही है। इससे शराबियों की आवाजाही बढ़ गई है और नशे में धुत लोग सार्वजनिक स्थानों पर गाली-गलौज, हुड़दंग और विवाद करते हैं। आए दिन होने वाले झगड़ों और मारपीट की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब बिक्री का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि शाम के समय घर से बाहर निकलना असुरक्षित महसूस होता है। कई परिवारों में शराब की वजह से घरेलू कलह बढ़ गई है, जिससे पारिवारिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है।

युवा पीढ़ी और गरीब परिवार हो रहे प्रभावित

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि गांव का युवा वर्ग तेजी से शराब की लत की ओर बढ़ रहा है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि आसान उपलब्धता के कारण किशोर और युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा शराब में खर्च हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है।

पहले भी हुई शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई

ग्रामीणों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी प्रशासन को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण ग्रामीणों में प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तीरथ ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेमेन्द्र साहू, युवा नेता अमिताभ राउत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि ग्राम सलखनी की चारों किराना दुकानों में कथित रूप से हो रही अवैध शराब बिक्री की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

समाजसेवी दयानंद ने हो रही वाहन दुर्घटनाओं को लेकर जनसुनवाई में सौंपे 80 आवेदन

छिंदवाड़ा। नगर निगम क्षेत्र में विशेषकर शहर के मुख्य मार्गों पर रोड पर रोड बनाने एवं उपर से डामरीकरण किये जाने के कारण रोड के उँचे होने से डिवाईडर नीचे होने के कारण दूरी से वाहन चालकों को डिवाईडर सामने से नहीं दिखने के कारण अक्सर ई.एल.सी. चैक, पंजाब लॉन नरसिंहपुर रोड, कलेक्ट्रेट रोड सहित शहर के अन्य स्थानों पर लंबे समय से दुर्घटनाओं को देखते हुये दयानंद चैरसिया द्वारा विगत लंबे समय से आमजन की सुरक्षा को देखते हुये इन डिवाईडरों को उंचा करने, रेडियम पट्टी अथवा सांकेतिक चिन्ह लगवाये जाने जिससे कि दूर से आने वाले टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर वाहनों को स्पष्ट दिखाई दे सके और आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से राहत मिल सके इस हेतु निरंतर आज दिनांक तक 80 आवेदन कलेक्टर जन सुनवाई सहित आयुक्त नगर पालिक निगम को दिये जा चुके हैं।

डेढ़ साल से अटके भुगतान, आवास सूची में सरपंचों की अनदेखी पर फूटा आक्रोश

परासिया सरपंच संघ ने एसडीएम व जनपद सीईओ को सौंपा ज्ञापन, लंबित भुगतान और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की उठाई मांग

हरिभूमि न्यूज ⏭ परासिया

परासिया सरपंच संघ की बैठक में ग्राम पंचायतों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद सरपंच संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी (एसडीएम) एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान, योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की।

सरपंच संघ के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव एवं सचिव मोहन कहार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सरपंचों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के संचालन के दौरान लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में अधिकारियों के निर्देश पर ग्राम पंचायत अंबाडा, इकलहेरा, भमोडी और जाटाछापर में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराई गई थी, लेकिन राहत शाखा द्वारा आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का सामग्री एवं अन्य मदों का भुगतान करीब डेढ़ वर्ष बाद भी लंबित है। भुगतान नहीं मिलने से सामग्री आपूर्तिकर्ता सरपंचों पर लगातार दबाव बना रहे हैं।

सरपंचों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे, सत्यापन और पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया से ग्राम पंचायतों को अलग रखने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि अपात्र हितग्राहियों की सूची कारण सहित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए तथा दावा-आपत्ति के माध्यम से छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएं, ताकि ग्रामीणों के बीच अनावश्यक विवाद की स्थिति न बने।

ज्ञापन में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्माण कार्यों के लिए समय पर स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, मूल्यांकन और पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके लिए समय-सीमा तय करने की मांग की गई।

सरपंचों ने यह भी कहा कि विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों और विकास यात्राओं के आयोजन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर डाल दी जाती है, लेकिन खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती। साथ ही शासकीय योजनाओं से संबंधित आदेश-निर्देश भी समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाते। उन्होंने प्रभारी पंचायत सचिवों की ग्राम पंचायतों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा मासिक उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर की व्यवस्था लागू करने की मांग की।

बैठक में सरपंच संघ अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव, सचिव मोहन कहार, भारती उईके, शक्ति भलावी, सीमा परानी, सुप्रिया पंद्राम, किसना मर्सकोले, शशि मर्सकोले, प्रकाश नवरेती, सावित्री पवार, गुरु प्रसाद, संतोष कवरेती सहित बड़ी संख्या में सरपंच उपस्थित रहे।

धनकशा में रोपे गए 62 हजार 500 पौधे, पेंच महाप्रबंधक ने श्रमिक नेताओं संग किया पौधा रोपण

परासिया : पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पेंच कोयला क्षेत्र के धनकशा में मंगलवार को ₹एक पेड़ माँ के नाम₹ अभियान के तहत वृहद पौधा रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया । जिसमें वेकोलि अधिग्रहित भूमि पर 62 हजार 500 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए ।कार्यक्रम का शुभारंभ पेंच कोयला क्षेत्र के महाप्रबंधक विकास कुमार अग्रवाल ने श्रमिक नेताओं और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रकार के फलदार और उपयोगी पौधे लगाकर किया । इस दौरान उन्होंने कहा , कि बढ़ते प्रदूषण और गर्मी को देखते हुए हर नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए । कोयलांचल क्षेत्र में हुए पौधा रोपण में मंगलवार को रौपे गए पौधों की संख्या बेहद ज्यादा है । इन पौधों को सुरक्षित बड़ा करना एक बड़ी जिम्मेदारी हैं । पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया इतना बड़ा कार्यक्रम तब ही फलिभूत और सफल होगा जब यह पौधे सुरक्षित बड़े होंगे । जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं , उनके लिए यह बड़ी जिम्मेदारी है ।

जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

सौंसर। मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भावना मलगाम को सौंपा गया। संगठन ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को रखते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने के दिए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। संविधान विरोधी माने गए यूसीसी (सीएए और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जैसे कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। मस्जिद, दरगाह, मदरसा, गुरुद्वारा, गिरजाघर और बौद्ध विहार जैसे धार्मिक संस्थानों पर हो रहे हमलों पर रोक लगाई जाए। जेलों में बंद बेगुनाह मौलानाओं और मुस्लिम नौजवानों को तुरंत रिहा किया जाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद (स.) पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी माँगें पूरी नहीं की गईं, तो देशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से सिराज शेख, विजय घाटोड, कृष्णा पहाड़े, सैफ अली, योगिराज वासनिक, धर्मेंद्र सोनेकर, अरुण बागड़े, जुबैर अली, प्रकाश सहारे, गोविंदा दुफारे, भगवान श्रीरामे, भीमराव सोमकूंवर और मनोहर गजभीए सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

नागद्वारी यात्रा की तैयारियों को लेकर आंबागिरी सेवा समिति की बैठक आयोजित

सौंसर। पवित्र श्रावण मास में आयोजित होनेवाली ऐतिहासिक नागद्वारी यात्रा एवं 17 अगस्त को पचमढी स्थित आंबागिरी में आयोजित विषाल भंडारे की तैयारियों को लेकर श्री नागद्वारी आंबागिरी सेवा समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में यात्रा को सुव्यवस्थित, भव्य एवं श्रद्धालुओं के लिये सुविधाजनक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिये समिति सदस्यासें को जिम्मेदारियां सौपी गई। जानकारी देते हुये समिति के पवन सरोदे ने बताया कि, 12 अगस्त से 17 अगस्त तक चलनेवाले इस धार्मिक आयोजन में महादेव यात्रा पर आनेवाले हजारों षिवभक्तों के लिये भोजन, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा एवं अन्य आवष्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जायेगी। समिति ने आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण समर्पण एंव सेवाभाव से कार्य करने का संकल्प लिया। अवसर पर षंकर खडसे, नरेन्द्र बोडखे, जीतू कोठेकर, प्रषांत बोबडे, अमोल मुंगोले, गोलू वाडेकर, संजय रेवस्कर, पवन बोडखे, अर्जुन श्रीखंडे, कुषल वानखेडे, गजनी घोडमारे, दिनेष चावके, अनमोल आकोटकर, अमर मानकर, आषीष भांगे, बाल्या श्रीखंडे, विनय गाडगे, षुभम बोडखे, साहिल भकने, अक्षय बोबडे, केवल बोबडे, लोकेष बोबडे एवं नानेष्वर बोबडे आदि उपस्थित थे। विदित हो कि, आंबागिरी सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष पचमढी के आमागिरी में भंडारे का आयोजन किया जाता है।

बरेलीपार ग्राम पंचायत के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला कटंगी में पेयजल का छाया संकट

जुन्नारदेव। शासकीय माध्यमिक विद्यालय कटंगी में पानी की गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा पी .एच. ई . विभाग की लापरवाही कई स्तरों से समस्या का निदान के लिए शिकायत की गई फिर भी विभाग चुपचाप सोया हुआ है।अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं चल रही है। शिक्षक के द्वारा सूचित करने पर भी एक सप्ताह तक कोई कार्रवाई नहीं करते हुए विभाग द्वारा हैंडपंप सुधार की व्यवस्था नहीं की गई। जिससे मध्यान भोजन संचालित करने में खाना पकाने में रसोइयों को एवं बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।पेयजल का गहरा संकट छाया हुआ है। जिसकी 181 में शिकायत करने पर भी अपना निवेदन पत्र प्रेषित करने के उपरांत भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इससे विभाग की एवं अधिकारियों की घोर लापरवाही प्रतीत होती है इसके लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा सूचित किया गया है। फिर भी विभाग मौन व्रत धारण किया हुआ है।

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सहित सभी ओबीसी संगठनों ने ओबीसी महासभा को समर्थन देते हुए किया घेराव

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

विगत दिनों भोपाल में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ एवं अन्य ओबीसी संगठनों ने ओबीसी महासभा को समर्थन देते हुये भोपाल विधानसभा क्षेत्र घेराव आंदोलन के साथ विशाल मोर्चा निकाला।

उक्ताशय की जानकारी जिला मीडिया प्रभारी संगीता दिलीप चरपे ने देते हुये बताया कि इस मार्च की मुख्य मांगो में 13 प्रतिशत होल्ड हटाने के साथ 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण जल्द लागू करने और जाति निकाय जनगणना सूची में ओबीसी वर्ग का स्वतंत्र कालम दर्ज किये जाने, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, राष्ट्रीय अध्यक्ष रत्नमाला पिसे के नेतृत्व में महासंघ मध्यप्रदेश के सभी जिलों से पदाधिकारियों की मुख्य उपस्थिति में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उपस्थित सामाजिक बंधुओं से अपील करते हुये कहा कि आगामी 7 अगस्त को बेंगलुरू में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महासंघ के 11 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर ओबीसी समाज की मांगो को अपना समर्थन दें । उन्होनें कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शासन एवं प्रशासन का सम्मान करता है तथा सरकार से आग्रह करता है कि जातीय जनगणना शीघ्र कराई जाए और ओबीसी वर्ग को उनका वाजिब संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाए। मोर्चे को सफल बनाने में राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष निरूपा प्रवीण ब्रम्हे, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शशि नंद , गोपाल साहू, सागर जिला अध्यक्ष रोहिणी रामेन्द्र साहू, जिला मंत्री लकी तुलसीराम चोरकर, जिला कोषाध्यक्ष शुभांगी विजय घोरसे, जिला महासचिव सुरेखा राकेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

उकवा के एकलव्य विद्यालय में पुलिस का नशा मुक्ति अभियान

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बोले- नशा ही नाश का कारण है

मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश पुलिस की संयुक्त पहल पर पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा के निर्देशन में जिले भर में 15 से 30 जुलाई तक ₹नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0₹ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को उकवा स्थित एकलव्य हायर सेकेंडरी स्कूल में बालाघाट पुलिस द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।

छात्र-छात्राओं ने किया अतिथियों का स्वागत

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव थे। उनके साथ थाना प्रभारी रूपझर कामेश धूमकेती, चौकी प्रभारी उकवा निरीक्षक सुभाष दुबे, उपनिरीक्षक हेमंत कुमार, विद्यालय के प्राचार्य अनिल सोलंकी तथा सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स बारीक एवं नितिन कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र-छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों के स्वागत से हुई।

नशा भविष्य को बर्बाद कर देता है : नितेश भार्गव

अपने संबोधन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने कहा कि छात्र जीवन ही भविष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा, खेल और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क, सोच और सपनों को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि नशे से दूरी ही सफलता की असली कुंजी है और युवाओं को हर परिस्थिति में इससे दूर रहना चाहिए।

अनुशासन और जागरूकता से ही मिलेगा नशे पर नियंत्रण

थाना प्रभारी कामेश धूमकेती ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार को भी प्रभावित करता है, जिससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं। चौकी प्रभारी निरीक्षक सुभाष दुबे ने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने और अनुशासित जीवन अपनाने का संदेश दिया। वहीं उपनिरीक्षक हेमंत कुमार ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध एवं नशे के नए रूपों से सतर्क रहने की सलाह दी।

पुलिस टीम की रही सक्रिय भूमिका

कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस चौकी उकवा की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान सहायक उपनिरीक्षक विनोद ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक दुर्गा प्रसाद बिसेन, प्रधान आरक्षक अनिल उइके, लेखराम उइके, तेजराम उइके, विद्यासागर पटले, आरक्षक टेकवन लिल्हारे सहित पुलिस बल एवं सहयोगी दल के सदस्य उपस्थित रहे।

नशामुक्त समाज के निर्माण का लिया संकल्प

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य अनिल सोलंकी ने पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। समापन अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं एवं उपस्थितजनों ने नशा मुक्ति की शपथ लेते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

चिरचिरा गांव में कीचड़ में निकली अंतिम यात्रा...

ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल

कटंगी। क्या इंसान की मौत हो जाए तो प्रशासन को फर्क नहीं पड़ता? शहरों में तो खूब सड़कें बन रही हैं। हमारे गांव के लिए कुछ नहीं हो सकता क्या? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है। यह कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम चिरचिरा के सैकड़ों ग्रामीणों का वह दर्द है जिसे वह बीते कई सालों से अपने सीने में दबाए हुए थे। मंगलवार को यह दर्द तब फूट पड़ा जब एक ग्रामीण की मौत के बाद उसका शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय ग्रामीणों को कीचड़ भरी कच्ची सड़क से गुजरना पड़ा। इसी दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और पूरे क्षेत्र में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी अनुसार मंगलवार सुबह चिरचिरा गांव में एक व्यक्ति के निधन के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण जब शव को श्मशानघाट ले जाने के लिए निकले। लेकिन गांव से श्मशान तक जाने वाली एकमात्र सड़क कच्ची और कीचड़ से लबालब थी। जिस कारण ग्रामीणों को परेशानियों को सामना करना पड़ा तो अंतिम यात्रा में शामिल किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जिम्मेदारों से सवाल किए।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्रामीण मिलकर अर्थी को उठाकर कीचड़ में फिसलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी के पैर कीचड़ में धंस रहे हैं तो कोई दूसरे का सहारा ले रहा है। इसी बीच एक ग्रामीण ने कैमरा ऑन कर पीड़ा रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में वह व्यक्ति कहता सुनाई दे रहा है - देखिए साहब, ये हालत हो गई है हमारी। गांव में एंबुलेंस नहीं आ पाती। बीमार हो जाए तो उसे 4 लोग कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। प्रशासन के उच्च अधिकारी, सरपंच साहब, विधायक साहब... सबको पता है पर कोई सुनता ही नहीं। चिरचिरा कटंगी तहसील से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव है। गांव के वरिष्ठ ग्रामीण बताते हैं, कई साल हो गए। हर चुनाव में नेता आते हैं, वादा करके जाते हैं कि अगली बार सड़क बनवा देंगे। वोट ले जाते हैं फिर 5 साल तक मुड़कर नहीं देखते। बरसात में तो यहां से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती। प्रसव के लिए महिलाओं को, या किसी गंभीर बीमार को खाट पर लिटाकर 1 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना हैं बड़े महानगरों में 4 लेन, 6 लेन सड़कें बन रही हैं और हमारें गांव में इंसान को अंतिम यात्रा के लिए भी कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कंधे पर लगाया स्टार

वनरक्षकों को मिली पदोन्नति, बनाए गए वनपाल

कटंगी। वन और वन्यजीवों की रक्षा में वर्षों से समर्पण के साथ ड्यूटी निभाने वाले वनरक्षक अमोल गौतम, एन.डी. शर्मा, गणेश शंकर नगरगढ़े, बादल जामुनकर, सतीश उइके, शशिकला चन्द्रवेल, ममता वट्टी को अब नई जिम्मेदारी मिली है। पदोन्नति के बाद यह सभी वनरक्षक से वनपाल बने हैं। सोमवार को नए पदनाम के साथ कंधे पर स्टार लगाकर इन्होंने अपने नए सफर की शुरुआत की। वन परिक्षेत्र कार्यालय में पदोन्नति के उपलक्ष्य में आयोजित छोटे से समारोह में वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चढ़ार ने सभी के कंधे पर वनपाल का स्टार लगाया और उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर वन विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। यह सभी पिछले कई वर्षों से कटंगी वन क्षेत्र में वनरक्षक के पद पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने जंगल की सुरक्षा, अवैध कटाई पर रोक, वन्यजीव संरक्षण और आग से बचाव जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और मेहनत को देखते हुए विभाग ने उन्हें वनपाल के पद पर पदोन्नत किया है। स्टार लगने के बाद सभी ने कहा कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वन, वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते रहेंगे। इनके अलावा दिलीप चौहान वनपाल से उपवन क्षेत्रपाल और राजेंद्र नगपुरे सहायक लिपिक वर्ग 3 से वर्ग 2 में

आध्यात्मिक जागृति और सामाजिक सुधार पर रहा जोर

कटंगी। मानव धर्म आंदोलन के केंद्रीय संगठन परमात्मा एक सेवक मंडल, वर्धमान नगर नागपुर के तत्वाधान में मंगलवार को ग्राम नांदी के बाजार चौक में मासिक नौवाँ हवन कार्यक्रम बड़े श्रद्धा भाव के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। भगवान बाबा हनुमान और मानव धर्म आंदोलन के प्रणेता महान त्यागी बाबा जुमदेवजी के छायाचित्र पर अतिथियों द्वारा पूजा-अर्चना और दीप प्रज्वलन कर हवन का शुभारंभ किया गया। शाम 4 बजे तक चले इस आयोजन में दूर-दूर से श्रद्धालु एकत्र हुए। कार्यक्रम के दौरान चार प्रमुख विषयों पर विशेष चर्चा की गई। आध्यात्मिक जागृति, सामाजिक सुधार, व्यसन मुक्ति और आर्थिक आत्मनिर्भरता। वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में समाज को नशे, अंधविश्वास और आपसी भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने की आवश्यकता है। परमात्मा एक सेवक मंडल की मुख्य शिक्षा को भी उपस्थित लोगों के सामने रखा गया। मंडल के अनुसार जीवन का आधार 'सत्य, मर्यादा, प्रेम, अनुशासन और मानवता' है। वक्ताओं ने बताया कि इन्हीं पांच स्तंभों पर चलकर ही व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान संभव है। हवन में तिरोड़ी और कटंगी तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में सेवक और सेविकाएं शामिल हुईं। महिलाओं और युवाओं की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। आयोजकों ने बताया कि हर महीने आयोजित होने वाला यह हवन कार्यक्रम समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और लोगों को व्यसनों से दूर कर स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।

खबर संक्षेप

हज के लिए आवेदन 24 जुलाई तक

हरिभूमि न्यूज सिवनी। वर्ष 2027 में हज यात्रा में जाने वालों के फार्म 24 जुलाई तक ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। आवेदन के लिए इंटरनेशनल पासपोर्ट जिसकी वैधता 31 दिस बर 2027 हो जरुरी है। शहर काजी मो.रफीक अंसारी, स्टेट हज ट्रेनर अल्हाज असदउल्ला खान, अफरोज खान मिस्त्री, हाजी अब्दुल वसी खान ने बताया कि 30 जुलाई को कुरा द्वारा यात्रियों को आरक्षित किया जाएगा। इसके उपरांत 10 अगस्त को हज की पहली किश्त 1 लाख 52 हजार 300 रूपए जमा करना होगा।

वसंतोत्सव समिति का सार्वजनिक अभिनंद कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम 25 को

हरिभूमि न्यूज सिवनी। सिवनी जिले की साहित्यिक संस्था वसंतोत्सव समिति के तत्वावधान में दिनांक 25 जुलाई 2026, दिन-शनिवार को दोपहर 5:00 बजे से नटराज पैलेस, तिकोना पार्क के सामने, कचहरी चौक, सिवनी में जिले के वरिष्ठ साहित्यकार अरविन्द अग्रवाल मानव के 75 वर्ष पूर्ण होने (हीरक जयंती) पर एवं समाजसेवी गणेश गुप्ता का सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सिवनी जिले के जाने-माने कवियों के द्वारा सरस कविता, गीत, गजल एवं व्यंग्य पाठ किया जायेगा।वसंतोत्सव समिति के समस्त पदाधिकारियों ने जिले के समस्त सम्माननीय नागरिकों से इस कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होने का विनम्र आग्रह किया है।

अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए बलराम तालाब योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

हरिभूमि न्यूज सिवनी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026-27 के लिए जिले को अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों हेतु बलराम तालाब निर्माण के कुल 4 लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें विकासखंड कुरई को 2, घंसौर को 1 तथा धनौरा को 1 लक्ष्य आवंटित किया गया है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि संबंधित विकासखंडों के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में पोर्टल आवेदन के लिए खुला है। आवेदन के लिए किसान के पास स्वयं की भू-स्वामी बही, खसरा नक्शा, बी-1 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं का फोटो तथा मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। किसान अपनी जोत सीमा के अनुसार अधिकतम 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तथा 2 हेक्टेयर से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। उपसंचालक ने पात्र किसानों से अपील की है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें।

अब तक जिले में 376.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जिले में मानसून की गतिविधियां लगातार जारी हैं। भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय द्वारा जारी दैनिक वर्षा प्रतिवेदन के अनुसार 01 जून से 21 जुलाई 2026 तक जिले में 376.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं 21 जुलाई को जिले में 20.5 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई। दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार 21 जुलाई को बरघाट तहसील में 9.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त कुरई में 17.0 मिमी, छपारा में 26.2 मिमी, सिवनी में 13.8 मिमी तथा घंसौर में 25.0 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं केवलारी में 45.0 मिमी, लखनादौन में 12.0 मिमी और धनौरा में 16.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 01 जून से 21 जुलाई तक हुई संचयी वर्षा के अनुसार बरघाट में 539.3 मिमी, केवलारी में 426.2 मिमी, सिवनी में 440.2 मिमी, लखनादौन में 418.4 मिमी, कुरई में 364.0 मिमी, छपारा में 322.6 मिमी, धनौरा में 270.0 मिमी तथा घंसौर में 229.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

सर्किट हाउस चौक पर सड़क बनी सब्जी मंडी, आये दिन हो रही दुर्घटना

नवनिर्मित सड़क पर सज रही दुकानें, संकरा हुआ मार्ग, कार्रवाई का इंतजार

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

जिला मुख्यालय का सबसे महत्वपूर्ण और वीआईपी मार्ग इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में है। सर्किट हाउस चौक से अंबेडकर चौक तक नवनिर्मित सडक़ के एक हिस्से पर प्रतिदिन सब्जी एवं अन्य अस्थायी दुकानों का बाजार सज रहा है। कलेक्ट्रेट गेट से महज 100 मीटर की दूरी पर सडक़ पर हो रहे इस कब्जे के कारण मार्ग संकरा हो गया है। नतीजतन यहां दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है और सडक़ दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है, कि सडक़ के एक ओर सब्जी विक्रेताओं के बैठने और ग्राहकों द्वारा सडक़ किनारे वाहन खड़े किए जाने से दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। कई बार दोनों ओर से वाहन आने पर लंबा जाम लग जाता है। कार्यालयीन समय और शाम के समय लोगों की अधिक आवाजाही होने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सबसे चिंता की बात यह है, कि इसी मार्ग से जिला अस्पताल आने-जाने वाली एम्बुलेंस भी गुजरती हैं।
विडंबना यह है कि इसी सडक़ से प्रतिदिन कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आवागमन होता है।
इसके बावजूद लंबे समय से सडक़ पर हो रहे इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई स्थायी कार्रवाई नहीं हो सकी है। कभी-कभार औपचारिक अभियान चलाकर दुकानों को हटाया जाता है, लेकिन अगले ही दिन सडक़ फिर बाजार में तब्दील हो जाती है।
इस स्थिति को लेकर लोगों में सवाल उठने लगे हैं कि जब जिला मुख्यालय के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पर ही अतिक्रमण और अव्यवस्था बनी हुई है, तो शहर के अन्य क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
नगरवासियों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि सर्किट हाउस चौक से अंबेडकर चौक तक सडक़ पर हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाकर स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो अनियंत्रित यातायात और जाम के कारण किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है

यूनिवर्सल कंप्यूटर एकेडमी के विद्यार्थियों ने BCA 6th Semester में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज सिवनी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCRPV), भोपाल से संबद्ध यूनिवर्सल कंप्यूटर एकेडमी, सिवनी के BCA 6th Semester के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हासिल कर संस्था का नाम गौरवान्वित किया है। संस्था में आयोजित परिणाम घोषणा के अनुसार अनुष्का बघेल ने 9.0 SGPA प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। महक सिंघानिया ने 8.8 SGPA के साथ द्वितीय तथा सृष्टि बर्वे ने 8.6 SGPA प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर संस्था प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रबंधन ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता उनके निरंतर परिश्रम, शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। संस्था ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी यूनिवर्सल कंप्यूटर एकेडमी के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्था एवं सिवनी जिले का नाम प्रदेश और देशभर में गौरवान्वित करेंगे।

JEE से NEET और फिर IISER तक... अमृता सिंह की सफलता का तिहरा धमाका

तीन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शानदार सफलता: अमृता सिंह ने बढ़ाया जिले का गौरव

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जिले की होनहार बेटी अमृता सिंह बघेल ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर लगातार तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। अमृता ने पहले जेईई में 97.30 पर्सेंटाइल प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद एनईईटी-यूजी परीक्षा में 720 में से 615 अंक अर्जित करते हुए ऑल इंडिया रैंक 6097 हासिल की। इसी सफलता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अमृता ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 303 प्राप्त की। एक के बाद एक तीन राष्ट्रीय परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन ने अमृता को जिले की मेधावी छात्राओं की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है।

अमृता सिंह ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और शुभचिंतकों के आशीर्वाद तथा निरंतर परिश्रम को दिया है। उनकी माता श्रीमती अंजू बघेल और पिता स्वराज सिंह बघेल, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष हैं, ने बेटी की इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
अमृता की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों तथा शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। जिलेवासियों का कहना है कि अमृता ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण और छोटे शहरों के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं।
लगातार तीन बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अमृता सिंह ने न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे सिवनी जिले का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने का उत्साह देगी।

आटो और बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर आटो पलटी 1 मृत 5 घायल

छपारा - 21 जुलाई दिन मंगलवार को नगर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम सुखामाल और ग्राम देवगांव के बीच क्रेशर के समीप सड़क पर एक भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई जिसमें छपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं एक स्कूली छात्रा सहित कुल 5 लोगों को चोटें आई जिसमें 63 वर्षीय भंवरलाल उईके को पैर में गंभीर चोट के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया मिली जानकारी के अनुसार छपारा नगर से एक आटो ग्राम घुनई होते हुए चमारी खुर्द की ओर जा रहा था कि दोपहर लगभग 3 बजे ग्राम मुंडरई सुखामाल के समीप मार्ग पर क्रेशर के पास सड़क पर सामने से एक बाइक सवार और आटो अनियंत्रित होकर टकरा गए जिसमें भंवरलाल उईके पिता बालचंद उईके 63 वर्ष ग्राम सुखामाल निवासी, सुरेश यादव पिता दयाराम यादव 24 वर्ष ग्राम इमलीपठार निवासी, सुरेश यादव अंधियारी , कुमारी सीता झारिया सुरेश यादव घायल हुए जिन्हें सूचना पर डायल 112 छपारा वाहन एक मौके पर उपस्थित जनों ने छपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान राजकुमार सल्लाम पिता प्रेम लाल सल्लाम 34 वर्ष इमली पठार बंजर निवासी की इस दुर्घटना में मौत हो गई वहीं पूरे मामले पर छपारा पुलिस द्वारा जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। वहीं भंवरलाल उईके को 108 ने जिला सिवनी चिकित्सालय पहुंचाया और सुरेश यादव को निजी वाहन से जिला चिकित्सालय रवाना किया गया।

ग्राम पंचायत सुनवारा में विकास के नाम पर बंदरबांट, सचिव नेपाल सिंह राठौर की मनमानी से ग्रामीण परेशान

धनौरा संवाददाता-केशव राय। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए भेजी जाने वाली राशि को जिम्मेदार अधिकारी किस तरह अपनी जेबों में भर रहे हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धनौरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुनवारा में देखने को मिल रहा है। यहां पदस्थ पंचायत सचिव नेपाल सिंह राठौर पर अपनी मनमानी करने और सरकारी फंड का जमकर दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बिना किसी डर के कागजों पर विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं।

कागजों पर चमकी पंचायत, जमीन पर विकास गायब

सूत्रो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत सुनवारा में बुनियादी सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में लाखों रुपये के काम दर्ज हो चुके हैं।
फर्जी मस्टर रोल और भुगतानः आरोप है कि पंचायत के निर्माण कार्यों में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर चहेतों के खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है।
अधूरे निर्माण कार्यः गांव में नाली निर्माण, सीसी रोड और भवनों को बेहद घटिया सामग्री से बनाए गए हैं, लेकिन इनका पूरा भुगतान निकाला जा चुका है।

हितग्राही मूलक योजनाओं में अड़ंगा

प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जब गरीब ग्रामीण पंचायत कार्यालय आते हैं, तो सचिव द्वारा उन्हें महीनों तक चक्कर कटवाए जाते हैं।
अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं सचिव— ग्रामीणों का फूटा गुस्साग्रामीणों ने सामूहिक रूप से आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सचिव नेपाल सिंह राठौर कभी समय पर पंचायत मुख्यालय नहीं आते हैं। जब भी कोई ग्रामीण अपनी समस्या या काम लेकर जाता है, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। सूत्रो का कहना है कि सचिव पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और अपनी मनमानी के चलते किसी भी जनप्रतिनिधि या वार्ड पंच की बात नहीं सुनते।

उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग

इस मामले को लेकर अब ग्रामीणों ने एकजुट होकर लामबंदी शुरू कर दी है। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) से मिलकर इस पूरे भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत सौंपने की तैयारी में है। ग्रामीणों की मांग है कि सचिव नेपाल सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पंचायत में पिछले कुछ वर्षों में हुए सभी निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। जांच के बाद दोषियों से सरकारी राशि की वसूली कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो।अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन गहरी नींद से जागता है या फिर सुनवारा पंचायत के ग्रामीण इसी तरह भ्रष्टाचार और मनमानी की चक्की में पिसते रहेंगे।

बरघाट को पुनः 100 बिस्तरीय अस्पताल किए जाने की मिली सौगात रेफर परंपरा में लग सकता है ब्रेक

राकेश अगरवार हरिभूमि बरघाट। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब जन प्रतिनिधि कमर कसते नजर आ रहे हैं कहा जाता हैं सुबह का भुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते हैं यही अब हुआ है विधानसभा बरघाट में जहां पर अब जनता का हमदर्द शिंकारा बनने के प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है देर आए दुरुस्त आए कहावत अब विधान सभा बरघाट में यह कहावत चरितार्थ हो रही है जहां पर आमजनो के स्वास्थ्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एक बार फिर से बरघाट अस्पताल को नई सौगात के रूप में 100 बिस्तरीय अस्पताल की सौगात मिलने की घोषणा हुई है सन 2017-18 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 20 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरघाट का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन कर भवन निर्माण हेतु 17 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की थी,लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल कर दिया था।

आम जनों के स्वास्थ्य सेवाओं की नई दिशा में 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बरघाट का पुन: 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किया गया है पुन: सुधार से बदलेगी बरघाट अस्पताल की तस्वीर

पूर्व समय में 100 बिस्तरीय अस्पताल का हुआ था वादा बना सिर्फ 50 बिस्तरीय

12 नवम्बर 2025 को लाड़ली बहना सम्मेलन सिवनी में बरघाट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कमल मर्सकोले के अनुरोध पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के उन्नयन की घोषणा की थी,घोषणा के परिपालन में 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का उन्नयन कर पुनः 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और विधायक कमल मर्सकोले के अथक परिश्रम कर सफलता प्राप्त किए जाने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया जा रहा है।

वर्तमान में पेसेंट रेफर समस्या से जूझ रहा अस्पताल बरघाट

जहां पर उल्लेखनीय होगा कि अल्प साधनों की वजह से महिलाओं को डिलीवरी के समय बरघाट विधानसभा के लोग तत्काल ही सिवनी जिला अस्पताल में रेफर किए जाने की पीड़ा से जूझ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं समाज की मूल आवश्यकता होती हैं और बेहतर चिकित्सा सुविधाओ का भी बढ़ेगा ग्राफ वर्तमान में बरघाट की अनेक वर्षों से रेफर परंपरा से जूझ रहा है जिस पर अब ब्रेक लगाने के प्रयास फलीभूत हो सकते हैं।

मिलावटी व सिंथेटिक दूध पर सिवनी में विशेष अभियान, डेयरी एवं दूध विक्रेताओं से लिए गए नमूने

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

महाराष्ट्र में सिंथेटिक एवं मिलावटी दूध के मामले सामने आने के बाद आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी एवं पदेन उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का विशेष जांच दल गठित कर विभिन्न डेयरियों, दूध विक्रेताओं एवं पनीर निर्माण स्थलों की सघन जांच की जा रही है।
इसी क्रम में सोमवार 21 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार परते, श्रीमती सोनू तिवारी, श्रीमती वंदना थागले एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों के विशेष जांच दल ने जिले के विभिन्न

प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान कुकलाहा स्थित साहू दूध डेयरी से पनीर का नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक मानकों से संबंधित कमियां पाए जाने पर संचालक को सुधार सूचना (इम्प्रूवमेंट नोटिस) जारी किया गया। जांच दल ने फुटकर दूध विक्रेताओं से भी नमूने लिए। संतोष कुमार साहू, कुकलाहा से गाय एवं भैंस के मिश्रित दूध का तथा कृष्ण कुमार ठाकुर, पलारी से दूध का नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की गई। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। विभिन्न दूध डेयरियों, पनीर निर्माण इकाइयों एवं फुटकर विक्रेताओं पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में मिलावटी अथवा अमानक दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित: कलेक्टर श्रीमती मीना ने प्रत्येक आवेदक से आत्मीय संवाद कर जानी समस्या

हरिभूमि न्यूज सिवनी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं एवं मांगों के समाधान की अपेक्षा लेकर पहुंचे।
कलेक्टर श्रीमती मीना ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, कृषि, पेंशन, पुलिस एवं अन्य विभागों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
जनसुनवाई में ग्राम चारगांव पीपरडाही निवासी श्रीमती कल्पना श्रीवास अपने बच्चे की दोनों आंखों में मोतियाबिंद के उपचार हेतु आर्थिक सहायता का आवेदन लेकर पहुंचीं। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बच्चे की विस्तृत स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने तथा

पात्रतानुसार शासन की संबंधित योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार डूंडा, सिवनी निवासी प्रेम नारायण ओझा ने गंभीर किडनी एवं लीवर रोग के उपचार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। कलेक्टर श्रीमती मीना ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक उपचार एवं पात्रतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
तहसील कुरई के ग्राम पीपरवानी निवासी रामेश्वरी देशमुख ने लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हुए अपने मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। कलेक्टर ने तहसीलदार कुरई को पटवारी के माध्यम से स्थल का सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार राहत प्रकरण तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि पात्रता के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसी क्रम में लखनादौन तहसील के ग्राम गौराबीबी निवासी प्रहलाद, इमरतलाल, महेश सहित अन्य किसानों ने जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट किए जाने पर मुआवजा दिलाने का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्रीमती मीना ने संबंधित तहसीलदार को प्रकरण की विस्तृत जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पात्र किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। सिवनी नगरीय क्षेत्र की स्वाति मर्सकोले ने उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने आवेदिका का उत्साहवर्धन करते हुए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) को आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कराकर पात्रतानुसार शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि आर्थिक अभाव उसकी पढ़ाई में बाधा न बने।

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना अंतर्गत 28 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

पैडी ट्रांसप्लांटर, रिजर एवं शुगरकेन रेटून मैनेजर यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

सहायक कृषि यंत्री, सिवनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चयनित कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। पात्र कृषक निर्धारित अवधि में आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के चयन हेतु 29 जुलाई 2026 को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

हरिभूमि न्यूज ⏭ सिवनी।

उन्होंने बताया कि इस चरण में पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप), पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड), रिजर तथा शुगरकेन रेटून मैनेजर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन के साथ कृषकों को अपने स्वयं के बैंक खाते से निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
निर्धारित धरोहर राशि पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (राइडिंग टाइप) – 15,000 रुपये ,पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (वॉक बिहाइंड) – 10,000 रुपये ,रिजर – 3,000 रुपये ,शुगरकेन रेटून मैनेजर – 5,000 रुपये है
सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए एग्री-स्टैक की फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। इसलिए जिन कृषकों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, वे पहले एग्री-स्टैक पोर्टल पर अपनी भूमि का पंजीयन कर फार्मर आईडी प्राप्त करें, तभी वे अनुदान योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि चयनित कृषि यंत्रों के क्रय हेतु कृषकों को जिला सहकारी बैंक, सिवनी से न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिले के कृषकों से समय-सीमा के भीतर आवेदन कर शासन की कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।

हरिभूमि

सतपुड़ा भूमि

तिरोड़ी | बोनकटा | कंटगी | बैहर | वारासिवनी | हटा

जबलपुर, बुधवार 22 जुलाई 2026

login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

वारासिवनी में नहर सफाई कार्य में बड़ा घोटाला

वारासिवनी। जल संसाधन विभाग वैनगंगा संभाग के अधर नहर अनुविभाग वारासिवनी में नहर सफाई कार्य में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से सफाई कराई गई। जिससे नहर कई जगह से टूट फूट गई और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक माइनर नहर खुर्सीपार से खैरी और खुर्सीपार से फोगल टोला तक सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावटी सफाई की गई है, जबकि अंदर गाद और कचरा जस का तस पड़ा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि काम सिर्फ कागजों में पूरा दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि ठेकेदार सावनकर बालाघाट ने मजदूरों को काम देने के बजाय मशीनों का उपयोग कर उनका हक छीन लिया। वहीं इस पूरे मामले मे कोमल गजभिये की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और अधिकारियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर भारत शिवहरे के द्वारा करीब एक महीने पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। खैरलांजी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद लिल्हारे ने चर्चा में बताया कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई, तो आंदोलन किया जाएगा। इस लापरवाही का सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। नहर सही तरीके से साफ नहीं होने के कारण सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही और भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से हुई थी भर्ती

रोजगार का वादा, वेतन पर ताला! एसएसयू के युवा बोले- चार माह से मुफ्त में करा रहे ड्यूटी, आखिर कब मिलेगा हक?

सात माह बाद भी नहीं मिला नियुक्ति पत्र- आईडी कार्ड, वेतन के लिए दर-दर की ठोकरें

हरिभूमि न्यूज़ लाँजी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बालाघाट की पहल पर गठित विशेष सहयोगी दस्ता (एसएसयू) अब गंभीर सवालों के घेरे में है। इस दस्ते में भर्ती किए गए युवक-युवतियों का आरोप है कि उनसे लगातार सरकारी कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन पिछले चार माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। हालात ऐसे हैं कि रोजगार मिलने की उम्मीद लेकर दस्ते से जुड़े कई युवा आज अपने ही खर्च पर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। एसएसयू से जुड़े कई युवाओं ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि उनकी भर्ती हुए करीब सात माह हो चुके हैं। भर्ती के बाद उन्हें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात कर नियमित सेवाएं ली जा रही हैं। पुलिस संबंधी कार्यों के अलावा डेम निर्माण जैसे कार्यों में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई। बावजूद इसके पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला।

घर से मंगाने पड़ रहे पैसे, बिना वेतन निभा रहे जिम्मेदारी

वेतन नहीं मिलने से एसएसयू के युवाओं की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका कहना है कि ड्यूटी के दौरान भोजन तक की व्यवस्था उन्हें अपने स्तर पर करनी पड़ रही है। कई युवा घर से पैसे मंगाकर गुजारा कर रहे हैं, जबकि कुछ ने टिफिन लगवा रखा है। रोजगार मिलने की खुशी अब चिंता में

बदल चुकी है। युवाओं का कहना है कि अगर समय पर वेतन नहीं मिलना था तो उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई।

न नियुक्ति पत्र, न पहचान पत्र... भविष्य पर भी संकट

युवाओं का सबसे बड़ा दर्द यह है कि भर्ती के महीनों बाद भी उन्हें न तो नियुक्ति पत्र दिया गया है और न ही पहचान पत्र। उनके पास ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वे विशेष सहयोगी दस्ता के सदस्य हैं। उनका कहना है कि यदि किसी दिन उन्हें सेवा से हटा दिया गया तो उनके पास अपने काम का कोई प्रमाण नहीं रहेगा। पीड़ित युवाओं ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी एसएसयू के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण उनकी शिकायत आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं नौकरी जाने के डर से अधिकांश युवा खुलकर सामने आने से बच रहे हैं।

अब सवाल यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की जिस पहल को सराहा गया था, क्या वही पहल अब प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ रही है? यदि युवाओं के आरोप सही हैं तो संबंधित विभाग को तत्काल स्थिति स्पष्ट करते हुए लंबित वेतन का भुगतान करना चाहिए और उनकी सेवा से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए। युवाओ ने संबंधित अधिकारी से शीघ्र ही उनकी वेतन दिलवाने, नियुक्ति पत्र सहित अधिकारिक दस्तावेज दिलवाने की मांग की है ताकि उन्हे पहचान भी मिल सके।

एसपी बोले- बजट प्रक्रिया के कारण हुई देरी, युवाओं का दर्द समझता हूं

विशेष सहयोगी दस्ता (एसएसयू) के युवाओं को वेतन नहीं मिलने के मामले में पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस समस्या की जानकारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन भुगतान में हुई देरी किसी की लापरवाही नहीं, बल्कि शासन की नियमित बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। एसपी मिश्रा ने बताया कि अप्रैल के बाद संबंधित बजट जारी नहीं हो सका। बजट स्वीकृत होने के बाद विभागों तक राशि पहुंचने में सामान्यतः तीन से चार माह का समय लगता है। जैसे ही शासन से राशि प्राप्त होगी, सभी एसएसयू जवानों को लंबित वेतन एकमुश्त जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि, मैं इन बच्चों की परेशानी और उनकी आर्थिक कठिनाइयों को समझता हूं। राशि शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी है और भुगतान होते ही सभी का वेतन दे दिया जाएगा।

कटंगी की श्री माता एचपी ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी पर कार्रवाई, स्टॉक में मिली भारी अनियमितता

बालाघाट। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.के. भलावी द्वारा गठित जांच दल ने 20 जुलाई 2026 को विकासखंड कटंगी के ग्राम जाम स्थित श्री माता एचपी ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान गैस सिलेंडरों के स्टॉक एवं अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर एजेंसी संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री पी.एस. वलाडी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश श्रीवास्तव (बैहर), श्रीमती निहारिका अवस्थी (वारासिवनी) एवं श्री तुषार सिंह (कटंगी) शामिल थे।

निरीक्षण के दौरान 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडरों में 211 खाली सिलेंडर अधिक तथा 243 भरे सिलेंडर कम पाए गए। वहीं 5 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडरों में 61 खाली सिलेंडर अधिक मिले। इसके अलावा 19 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में 3 खाली सिलेंडर अधिक एवं 5 भरे सिलेंडर कम पाए गए। 5 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में 11 खाली सिलेंडर अधिक तथा 114 भरे सिलेंडर कम पाए जाने की पुष्टि हुई। जांच में प्रथम दृष्टया गैस वितरण एवं प्रदाय में अनियमितता, स्टॉक का नियमित रखरखाव एवं संधारण नहीं किए जाने सहित अन्य खामियां भी पाई गईं। इन अनियमितताओं के आधार पर श्री माता एचपी ग्रामीण वितरक, जाम के प्रोपराइटर महेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

थाना रूपझर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़, उकवा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बैहर के मार्गदर्शन में थाना रूपझर पुलिस ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत लंबे समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय न्यायालय बैहर के प्रकरण क्रमांक 873/2016, धारा 9, 49, 51 एवं 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत आरोपी भृतु पिता जंगलू मरकाम (उम्र 48 वर्ष), निवासी ग्राम नारंगी, थाना रूपझर के विरुद्ध दिनांक 05 अगस्त 2025 को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। दिनांक 21 जुलाई 2026 को थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर ग्राम लागमा एवं नारंगी में दबिश दी। पहचान की पुष्टि होने के बाद आरोपी को विधिवत गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को देकर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस सफल कार्रवाई में प्रधान आरक्षक 982 संतोष मरकाम, आरक्षक 1458 अवन सिंह उइके, आरक्षक 168 शिवराज उइके, आरक्षक 221 अभिषेक कोठी, आरक्षक 1100 कृष्णकुमार यादव, आरक्षक 96 जितेन्द्र मराठे तथा एसएएफ बल के अर्जुन मरावी एवं सुरेश मरावी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सराहनीय भूमिका:

इस संपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक कामेश धुर्वे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए आरोपी की सफल गिरफ्तारी सुनिश्चित की। टीम के सभी सदस्यों के समर्पण एवं सक्रियता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की गई।

पुलिस ने बस स्टैंड में चलाया नशे से दूरी है जरूरी,

हरिभूमि न्यूज़ वारासिवनी। स्थानीय बस स्टैंड परिसर में वारासिवनी पुलिस की ओर से जन जागरूकता के उद्देश्य से एक नुक्कड़ अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और राहगीरों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। यह जागरूकता अभियान सहायक उप निरीक्षक हेमलता शुक्ला, प्रधान आरक्षक रामप्रसाद भरने एवं आरक्षक ओमकार उइके सहित पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने नशे से दूरी है जरूरी, विषय पर उपस्थित जनसमुदाय को अत्यंत सारगर्भित और प्रभावी ढंग से समझाया। पुलिस टीम ने बस स्टैंड पर मौजूद लोगों, यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखू, गुटका, शराब व अन्य हानिकारक नशीली वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य और परिवार दोनों के लिए अत्यंत घातक है। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और धूम्रपान से होने वाली बीमारियों तथा इससे समाज पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के प्रति विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं को व्यसनमुक्त रखें और अपने आसपास के लोगों को भी नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करें।

नशे के खिलाफ सितापाला चौकी की पहल, स्कूली बच्चों को दिलाई नशामुक्ति की शपथ

हरिभूमि न्यूज़ र, लाँजी। जिले में चलाए जा रहे नशामुक्ति जनजागरूकता अभियान के तहत बहेला थाना क्षेत्र की सितापाला चौकी पुलिस ने प्राथमिक शाला टाटीकला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। इस अवसर पर सभी ने नशे से दूर रहने तथा समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, शिक्षा, भविष्य और समाज को भी प्रभावित करता है। इसलिए बचपन से ही नशे के प्रति जागरूकता आवश्यक है। विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहना ही स्वस्थ और सफल जीवन की पहली शर्त है। पुलिस ने बच्चों से

आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने घर-परिवार एवं आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक करें। साथ ही किसी भी प्रकार की अवैध नशे की गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई।कार्यक्रम के अंत में प्राथमिक शाला टाटीकला के सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यालय स्टाफ को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे और समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। विद्यालय परिवार ने पुलिस के इस जनहितकारी अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम बच्चों में सकारात्मक सोच विकसित करने के साथ-साथ समाज में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिलेभर में नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और स्कूलों, गांवों तथा सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

विधानसभा में गूंजा बालाघाट की रेत का मुद्दा, विधायक मधु भगत ने ग्राम पंचायतों को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध कराने की उठाई मांग

बालाघाट। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बालाघाट जिले में रेत की गंभीर समस्या का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहे संकट की ओर आकर्षित किया। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 770 के माध्यम से वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान जिले की रेत खदानों की स्थिति, निविदा प्रक्रिया, स्वीकृत ठेकों, संचालित रेत घाटों तथा वर्तमान व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारी सरकार से मांगी।विधायक मधु भगत ने सदन में कहा कि बालाघाट जिले में अधिकांश रेत खदानों के ठेके समाप्त हो जाने और लंबे समय से नई स्वीकृतियां जारी नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी बन गई है कि पंचायतें स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पा रही हैं और ग्रामीणों को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है।उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क निर्माण, सीसी रोड, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन तथा अन्य बुनियादी विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि रेत की अनुपलब्धता के कारण कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुए हैं, वे भी समय पर निर्माण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है

और पंचायतों पर भी अनावश्यक दबाव बन रहा है।विधायक भगत ने सरकार को याद दिलाया कि वर्ष 2013-14 में ऐसी व्यवस्था लागू थी, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास कार्यों और आम जनता की आवश्यकताओं के लिए निर्धारित एवं आसान दरों पर रेत उपलब्ध कराई जाती थी। उस व्यवस्था से पंचायतों को निर्माण सामग्री प्राप्त करने में सुविधा मिलती थी तथा विकास कार्य बिना किसी बाधा के संचालित होते थे। उन्होंने मांग की कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसी प्रकार की व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल सके और लोगों को राहत मिल सके।उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में रेत की कमी के कारण निर्माण कार्यों की लागत भी बढ़ रही है। जहां कहीं निजी स्तर पर रेत उपलब्ध हो रही है, वहां उसकी कीमत आम लोगों और पंचायतों की पहुंच से बाहर है। इससे गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को मकान निर्माण में अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पंचायत स्तर पर नियंत्रित और पारदर्शी व्यवस्था लागू करती है, तो अवैध उत्खनन पर भी प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी और ग्रामीणों को उचित दरों पर रेत उपलब्ध होगी।विधानसभा में विधायक मधु भगत द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को बालाघाट जिले की लंबे समय से चली आ रही एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा रहा है। जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार रेत की कमी और विकास कार्य प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का भी कहना है कि रेत उपलब्ध नहीं होने के कारण कई स्वीकृत निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। विधायक भगत ने सरकार से आग्रह किया कि बालाघाट जिले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ठोस निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित दरों पर रेत उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रधानमंत्री आवास सहित सभी विकास कार्यों में तेजी आए, ग्रामीण जनता को राहत मिले और शासन की योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस महत्वपूर्ण जनहित के विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करेगी।